विचार कर्म का बीज है

डिजिटल युग की चुनौती

डाटा चोरी मामले में कैंब्रिज एनालिटिका और फेसबुक को दूसरी नोटिस देने की नौबत आई तो इसका मतलब है कि पहले नोटिस से बात नहीं बनी। ऐसा लगता है कि ये दोनों कंपनियां अपनी जवाबदेही को लेकर गंभीर नहीं। एक ओर जहां कैंब्रिज एनालिटिका ने कामचलाऊ जवाब देकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली वहीं दूसरी ओर फेसबुक खेद जताने और भविष्य में ऐसा न होने देने का आश्वासन भर देने तक सीमित रही। यह ठीक है कि भारत सरकार ने दूसरा नोटिस जारी कर यह संकेत दिया कि वह कोई सख्त फैसला भी ले सकती है, लेकिन केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है। यह वक्त की मांग है कि सरकार डाटा चोरी रोकने के लिए कोई ठोस कानून बनाए। ऐसे कोई कानून इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि कल को कोई अन्य कंपनी वैसा ही काम कर सकती है जैसा फेसबुक की लापरवाही से कैंब्रिज एनालिटिका ने किया। चूंकि अब यह खतरा बढ़ गया है कि लोगों का डाटा चुराकर और राजनीतिक, सामाजिक मामलों में उनकी रुचि जानकर उन्हें मिथ्या प्रचार से प्रभावित करने का काम किया जा सकता है इसलिए फेसबुक और कैंब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनियों को किन्हीं नियम-कानूनों में बांधने की जरूरत है। सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती और न ही उसे करना चाहिए कि नियम-कानूनों के अभाव में राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के लिए काम करने वाली कंपनियां चुनावों को प्रभावित करने और यहां तक कि किसी संवेदनशील मसले पर लोगों को उकसाने या बरगलाने का भी काम कर सकती हैं। जब यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरह का काम होने लगा है तब फिर भारत को डाटा सुरक्षा के मामले में वैसे ही कानून बनाने चाहिए जैसे यूरोपीय समुदाय ने बनाए हैं। यह ठीक नहीं कि फेसबुक की ओर से यह कहा जा रहा है कि वह डाटा सुरक्षा के वैसे प्रबंध नहीं कर सकती जैसे उसने यूरोपीय समुदाय के लिए किए हैं। क्या इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत को दोयम दर्जे के देश के तौर पर देख रही है और वह भी तब जब भारत एक बड़ी डिजिटल ताकत के तौर पर उभर रहा है?

डाटा चोरी रोकने के लिए सक्षम कानून बनाने के साथ ही यह भी समझने की आवश्यकता है कि मुफ्त में सूचनाएं और जानकारी प्रदान करने वाली इंटरनेट आधारित कंपनियां उपभोक्ताओं का डाटा किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करती ही हैं। शायद इसीलिए यह कहा गया है कि लोग जिन सेवाओं का मूल्य नहीं चुकाते उनके उत्पाद वे स्वयं होते हैं। डिजिटल युग की इस हकीकत के बावजूद उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि उनकी निजी जानकारी का उपयोग कौन किसलिए कर रहा है? इस मामले में यह भी ध्यान रहे कि आज के डिजिटल युग में ऐसी अपेक्षा का कोई मतलब नहीं कि डाटा यानी निजी जानकारी का किसी भी रूप में कहीं कोई इस्तेमाल ही न होने पाए। आधार पहचान पत्र के मामले में कुछ लोग इसी अपेक्षा के साथ कुतर्क करने में लगे हुए हैं। डाटा के मामले में निजता के अधिकार को जरूरत से ज्यादा खींचना एक तरह की डिजिटल अज्ञानता ही है।

सराहनीय निर्णय

कभी ऐसा समय था जब इंटरव्यू के नाम से मेधावी विद्यार्थियों के भी पसीने छूट जाते। महीनों पहले से तैयारी होने लगती और पूर्व में परीक्षाएं पास कर चुके लोगों की शरण ली जाती। वे बताते कैसे कमरे में प्रवेश करना है और भले ही अंदर से कांप रहे हो पर कैसे परीक्षक के सामने अपने को आत्मविश्वास से लबालब प्रदर्शित करना है। सवालों की तैयारी होती और कपड़ों का चुनाव होता। इंटरव्यू का दिन अपने लिए रहस्य और रोमांच का ऐसा अनोखा अवसर उपलब्ध कराता जिसका आनंद वही ले सकता है जिसने किसी भी भूमिका में इसे साक्षात अनुभव किया हो। यह स्थिति अब बदल गई है।

अपने सुखद भविष्य के लिए बच्चे दिन रात झोंक देते हैं। उनके सपनों से उनके परिवार के सपने जुड़े होते हैं

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू के नंबर दो सौ से घटाकर सौ करने का निर्णय क्या किया, हजारों विद्यार्थी खुश हो उठे और फैसले की चौतरफा सराहना होने लगी। कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानी नहीं चलेगी और योग्यता का मापदंड लिखित परीक्षा पर अधिक केंद्रित होगा। केवल यह एक बात यह बताने के लिए काफी है कि थोड़ा अरसा पहले तक आयोग में भर्तियां किस तरह की जाती रही हैं। पुरानी व्यवस्था में अधिकतम 140 और न्यूनतम 80 अंक दिये जाते। इससे कम या अधिक देना हो तो आयोग से पूछने का नियम था। बस, इसी का लाभ उठाकर नंबर बांटे गए। लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले कितने ही छात्र इंटरव्यू में कम अंक पाने के कारण परीक्षा पास नहीं कर सके। इससे उलट वे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए जिन्हें लिखित में तो कम नंबर मिले थे लेकिन, इंटरव्यू में जिन पर आयोग की कृपा बरस गई। अपने सुखद भविष्य के लिए बच्चे दिन रात झोंक देते हैं। उनके सपनों से उनके परिवार के सपने जुड़े होते हैं। इन बच्चों को धोखा देना मानवता को धोखा देना है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

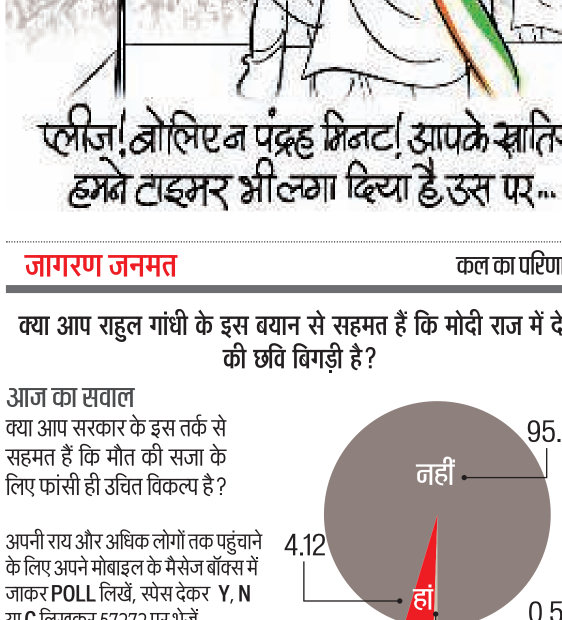

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं कि मोदी राज में देश की छवि बिगड़ी है?

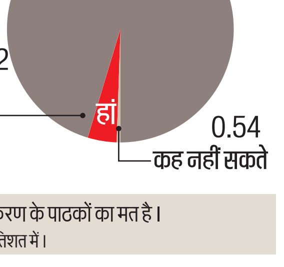

आज का सवाल

क्या आप सरकार के इस तर्क से सहमत हैं कि मौत की सजा के लिए फांसी ही उचित विकल्प है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अप्रत्याशित दौरे से बढ़ी उम्मीदें

विवेक काटजू

अगर मोदी चीनी राष्ट्रपति की सोच में ऐसा कोई बदलाव ला सकें जो चीन की नीतियों में भी दिखे तो यह एक बड़ी सफलता होगी

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ दो दिवसीय अनौपचारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी मोदी को जून में चीन जाना है, ऐसे में उससे पहले 27 अप्रैल को उनका वहां जाना अप्रत्याशित ही है। चूंकि मोदी विशेष रूप से यह दौरा कर रहे इसलिए यह उम्मीद स्वाभाविक है कि दोनों नेता रिश्तों को एक नई दिशा देंगे और उनकी मुलाकत से कुछ ठोस नतीजे निकलेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि कि सम्मेलन में आखिर किन बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? हालांकि वांग ने कहा कि चीन यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि अनौपचारिक बैठक पूरी तरह कामयाब रहे और द्विपक्षीय रिश्तों में मील का पत्थर साबित हो। क्या सफलता का अर्थ यह है कि द्विपक्षीय रिश्ते चीनी आक्रामकता से पैदा हुए डोकलाम विवाद से पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगे या फिर चीन सहयोग के नए नजरिये के साथ आगे बढ़ने का इच्छुक है और इसमें वह भारत के हितों को पूरी तवज्जो देगा? यह अच्छा संकेत है कि दोनों देशों ने डोकलाम में पैदा हुए तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए। हालांकि ऐसी खबरें भी आईं कि बाद में चीन ने उस इलाके में निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो अपने हितों को देखते हुए भारत को भी वहां निगरानी बढ़ानी पड़ी।

इस साल फरवरी से ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले जैसे शीर्ष अधिकारी चीनी पक्ष के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। एससीओ में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की उस बैठक के लिए सुषमा स्वराज के बीजिंग दौरे से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी जिसमें सम्मेलन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। वांग के साथ बैठक में सुषमा स्वराज ने आंतकवाद विरोधी अभियान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और हेल्थकेयर जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी का कोई उल्लेख नहीं था। पिछले कुछ महीनों में भारत ने भी दलाई लामा को लेकर चीन की आपत्तियों को खासी तवज्जो दी है। तिब्बतियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से सरकार और उसके अधिकारियों ने दूरी बनाए रखी। मोदी-चिनफिंग सम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब अंतरराष्ट्रीय संबंध भारी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका की तरह महाशक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए चीन हरसंभव कोशिश में लगा है। उसने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का प्रारूप ऐसा बनाया है कि उसे अपने साथ कुछ पिछलग्गू देश मिल जाएं। चीन को लेकर अपने तमाम विरोधाभासी बयानों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भ्रम ही पैदा करते हैं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीन की चुनौती का तोड़ निकालने के लिए अमेरिका कुछ कदम जरूर उठा रहा है। चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। चीन की काट के लिए अमेरिका भारत जैसे देशों के साथ सामरिक रिश्तों को मजबूत बना रहा है। स्वाभाविक रूप से चीन नहीं चाहेगा कि भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में चला जाए।

अवधेश राजपूत

बीते कुछ समय से दुनिया भर में भारत को एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर स्वीकृति मिलती जा रही है। मोदी के हालिया स्टॉकहोम दौरे के दौरान स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत एक वैश्विक दिग्गज के रूप में उभरा है। चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या सतत विकास, कोई भी प्रमुख वैश्विक विमर्श भारत की राय के बिना पूरा नहीं होता।' चीन भी भारत के अंतरराष्ट्रीय कद की अनदेखी नहीं कर सकता जो डोकलाम विवाद के दौरान मोदी के दृढ़ एवं संयत रुख के चलते और बढ़ा ही है। ध्यान रहे कि इस दौरान चीन की टीका-टिप्पणियां और रुख उकसाने वाला ही था। सुषमा स्वराज और वांग यी ने बैठक के बाद कहा कि मोदी और चिनफिंग उन दीर्घावधिक और रणनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे जिनका वास्ता भविष्य के संबंधों से होगा। भारत-चीन संबंधों के साथ ही यह समूचे क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक ही कहा जाएगा। इस दौरान मोदी को भी अवसर मिलेगा कि वह चीन के साथ बेहतर संबंधों की दिशा में भारत की आवाज बुलंद करें। यह क्षेत्रीय और वैश्विक हित में होगा। इसके साथ ही चीन को भी यह मंशा जाहिर करनी होगी कि वह सीमा विवाद को सुलझाने के प्रति गंभीर है। उसे भारत के साथ बराबरी का आर्थिक एवं वाणिज्यिक रिश्ता बनाना होगा। जाहिर है कि इसके लिए उसे अपने बढ़-चढ़कर किए जाने वाले उन दावों से पीछे हटना पड़ेगा जिनकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं होती।

भारत-चीन रिश्तों में तमाम बाधाएं इसलिए हैं, क्योंकि चीन आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की ढाल बना हुआ है। इसमें एनएसजी सदस्यता का मुद्दा भी शामिल है। बीते दिनों लंदन में भारतवंशियों के साथ बातचीत में मोदी ने पाकिस्तान को आतंक का निर्यातक करार दिया तो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन ने आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ने में पाकिस्तान का बचाव किया। अभी तक चीन ने यह भी संकेत नहीं दिए हैं कि वह मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करेगा या नहीं? अगर अब वह इस प्रस्ताव का समर्थन करता भी है तो भारत को इसे बहुत बड़ी मेहरबानी के तौर पर नहीं देखना चाहिए।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी से जुड़े अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों को देखते हुए चीन पाकिस्तान के साथ सभी मोर्चों पर रिश्ते मजबूत बना रहा है। चीन-पाकिस्तान के रिश्तों की बुनियाद अभी तक भारत के प्रति साझा नकारात्मकता पर टिकी हुई थी, लेकिन सीपीईसी ने इन रिश्तों को एक नया आधार दिया है। चीन को डर है कि भारत पाकिस्तान विरोधी बलूच समूहों और अन्य तत्वों को शह देकर उसका खेल बिगाड़ सकता है। रणनीतिक रूप से भारत ऐसा कर तो सकता है, लेकिन उसने चीनी हितों के खिलाफ कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सम्मेलन के दौरान सीपीईसी के मोर्चे पर कोई नई बात सामने आती है या नहीं? अगर मोदी चिनफिंग की सोच में बदलाव ला सकते हैं और यह बदलाव उनकी नीतियों में भी दिखता है तो यह इस सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता होगी। इसी तरह अगर चुनावी साल के पहले सीमा पर शांति को लेकर सहमति बनती है तो इसे भी सराहनीय कहा जाएगा। इस सबके बीच भारत को अपने रक्षा मोर्चे को और मजबूत बनाना होगा और साथ ही जापान एवं अन्य एशियाई देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने होंगे। उसे अपने उन पड़ोसी देशों में भी अपनी पैठ बनानी होगी जहां चीन उसे घेरने के लिए घुसपैठ कर रहा है। मालदीव इसका ज्वलंत उदाहरण है तो श्रीलंका में भी चीनी निवेश भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है। इसी तरह नेपाल भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वहां भी चीन का तोड़ निकालना होगा। इस सम्मेलन की मंशा स्वागतयोग्य है, लेकिन भारत किसी मोर्चे पर ढील नहीं दे सकता।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

झूठ के सहारे पर टिकी राजनीति

राजनाथ सिंह 'सूर्य'

कांग्रेस इस सोच से ग्रस्त दिखती है कि अतीत के आचार-विचार नष्ट किए बिना नया समाज नहीं खड़ा किया जा सकता

ऐसा लगता है कि अब भाजपा को कांग्रेस मुक्त अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतः भारत को कांग्रेस मुक्त करने की दिशा पकड़ ली है। वह शायद अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करते-करते कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच गई। निर्वाचन आयोग को पक्षपाती करार देने और संसद को हुल्लड़बाजी का अखाड़ा बनाने के बाद जज लोया की स्वाभाविक मौत को हत्या बताकर उसे जिस सीमा तक विस्तार दिया गया उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इस मामले में जब मनमाफिक फैसला नहीं मिला तो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आया गया। यह काम जिस आनन-फानन तरीके से किया गया उससे यही लगता है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने चुनाव जीतने के लिए भारत में अनास्था का बवंडर खड़ा करने का जो उपाय सुझाया था उस पर अमल किया जा रहा है। सत्ताधारी दल कितनी भी सावधानी बरते, शासन संचालन में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। उन कमियों को उजागर करने के बजाय काल्पनिक मुद्दों को झूठ के सहारे आगे बढ़ाने से क्षणिक भ्रम भले ही पैदा हो, कोई दूरगामी परिणाम नहीं मिलता। उलटे वह ऐसा करने वालों के खिलाफ ही जाता है। महाभियोग मामले में ऐसा ही हुआ। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा सभापति की टेबल से आगे भी नहीं जा पाया और कांग्रेस को खरी-खोटी अलग से सुननी पड़ी। इसके पहले कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को लांछित करने की कोशिश की थी, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद झूठ पर टिका यह मसला उसके हाथ से निकल गया।

सत्ता में रहकर कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का जो मसला खड़ा किया था उसी का परिणाम 2014 के चुनाव में देखने को मिला था। अस्सी प्रतिशत आबादी को संदेह के कठघरे में खड़ा करने के परिणामों की अनदेखी कर कांग्रेस ने न केवल अपने को जनमान्यता में सबसे नीचे पायदान पर पहुंचा दिया, बल्कि देश के माहौल को भी विषाक्त बना दिया। एक अर्से से वह इस पर व्यस्त है कि अगर कहीं चींटी भी दबकर मर जाए तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को दोषी बताना है। इस आदत ने कांग्रेस की नीयत और नीति, दोनों को बेनकाब किया है। जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह कहते हैं कि मोदी उनके सामने 15 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते तो उनकी इस बात पर हंसी भी नहीं आती। जहां मोदी बिना पर्ची के सहारे किसी विषय पर घंटे भर से भी अधिक वक्तव्य देते हुए बार-बार देखे गए हैं वहीं राहुल गांधी बिना पर्ची के सहारे 15 मिनट तक भी बोलते नहीं दिखाई पड़ते और यह स्पष्ट ही है कि पढ़कर दिया जाने वाला भाषण किसी को प्रभावित नहीं करता। इस पर यकीन करना कठिन है कि सगे-संबंधियों सहित घोटाले में फंसा कांग्रेस नेतृत्व संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना की राह पर आगे बढ़ता हुआ मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक चला गया और वह भी बिना किसी ठोस आधार के। कांग्रेस एक बार फिर 1975 के समान न्यायालय की अवमानना करती दिखी। कांग्रेस को पता होना चाहिए था कि उसके इस कदम की सर्वत्र भर्त्सना होगी। फली नरीमन और सोली सोराबजी जैसे विधि विशेषज्ञों ने जिस स्वर में इस कदम की भर्त्सना की वह उसकी आंख खोलने के लिए काफी होना चाहिए।

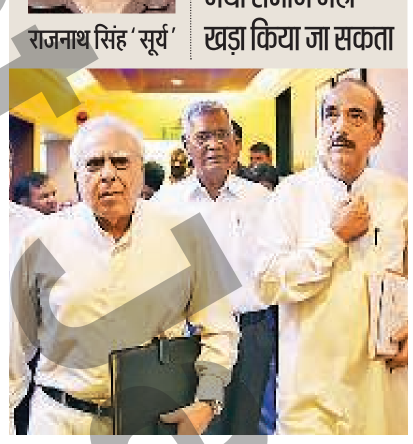

कहीं महाभियोग प्रस्ताव का मकसद मुख्य न्यायाधीश को भयभीत करना तो नहीं था ताकि जो मामले उनके समक्ष विचाराधीन हैं उनके बारे में वह किसी नतीजे पर पहुंचने से डर जाएं। ध्यान रहे कि विचाराधीन मामलों में अयोध्या मसला भी है। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील की हैसियत से कांग्रेसी सांसद एवं वकील कपिल सिब्बल ने जो दलील दी थी उसी में सारा रहस्य छिपा है। उन्होंने न्यायालय में जोर देकर कहा था कि इस मामले की सुनवाई 2019 के आम चुनाव तक टाल दी जाए। इसके पक्ष में वह कोई सार्थक तर्क नहीं दे सके। अक्टूबर में अवकाश प्राप्त कर रहे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। यदि यह पीठ फैसला कर देती है तो उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है, भले ही फैसला कुछ भी हो। इससे एक बात और साफ है कि अयोध्या मामले में साक्ष्यों के आधार पर जिस प्रकार का फैसला आने की उम्मीद है उससे कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक दुकानें बंद होने की चिंता सता रही है। इसी चिंता में ही वे अयोध्या मामले को लटकाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस भी इसी में अपना राजनीतिक हित देख रही है। ऐसे लोगों ने ही तीन तलाक संबंधी विधेयक को राज्यसभा से पारित नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों ने बैंकों से लोन लेकर विदेश भाग जाने वालों की संपत्ति जब्त करने संबंधी विधेयक में भी अड़ंगा लगाया। अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न कानून पर भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को जातीय-वर्गीय तनाव बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दोष भी मोदी सरकार पर मढ़ने की कोशिश हुई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस साम्यवादी सिद्धांत का शिकार हो गई है कि अतीत के सामाजिक शिष्टाचार और राजनीतिक आचार-विचार को नष्ट किए बिना नया समाज नहीं खड़ा किया जा सकता। शायद इसीलिए निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय को संदिग्ध साबित करने और उनकी साख मिट्टी में मिलाने का अभियान चल रहा है। कभी-कभी तो लगता है कि कांग्रेस मार्क्सवादी चुनावी रणनीति का एक मोहरा भर बनकर रह गई है। कांग्रेस उन वकीलों को भी मोहरे की तरह इस्तेमाल करती दिख रही है जो बात-बात पर जनहित याचिका दायर करते रहते हैं। ये वे वकील हैं जो वैचारिक तौर पर अंध मोदी विरोध से ग्रस्त हैं। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को संदेह है कि ये वकील अदालत का सहारा लेकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की हद तक जा सकते हैं।

राजनीतिक संस्था के रूप में कांग्रेस अपनी मान्यता खो रही है। वह छीना-झपटी करने वालों के समान असावधान लोगों पर हाथ साफ करने में लगी है। इसका आभास इससे भी मिल है कि कई कांग्रेसी नेताओं ने भी महाभियोग प्रस्ताव को अनुचित बताया। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को घेरने की कोशिश के तमाम पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अयोध्या मामला, जिसे कांग्रेस हल होते नहीं देखना चाहती। एक ओर वह इस मसले के हल में अड़ंगा भी डाल रही है और दूसरी ओर रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय भी लेती है।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धैर्य

मनुस्मृति में धैर्य को धर्म का सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। संत कबीरदास ने जीवन में धैर्य को प्राथमिकता दी है। धैर्य का यह मतलब कतई नहीं होता कि मनुष्य अपना कर्तव्य करना छोड़ दे, बल्कि इसके सार्थक मायने यह हैं कि मनुष्य को व्याकुल व परेशान हुए बगैर अपने कर्म को संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। धैर्य और संतुलन सच्चे मित्र हैं। धैर्यवान व्यक्ति सदैव अपने आप को संतुलित अवस्था में बनाए रखता है। संतुलित मन उचित तरीके से और गहराई में उतरकर किसी भी कथन पर चिंतन कर सकता है। धैर्य सकारात्मक ऊर्जा है, जो दिखती तो नहीं है, परंतु मनुष्य को आंतरिक सुख और शीतलता अवश्य प्रदान करती है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नशा व कामुकता ऐसे नकारात्मक तत्व हैं जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। मस्तिष्क को चेतनाशून्य कर देते हैं, जिसकी आड़ में इंसान अपना विवेक खो बैठता है और जिसके परिणामस्वरूप अराजकता रूपी दलदल में फंसता चला जाता है। मनुष्य का यह बहुमूल्य जीवन विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। इस संसार में जो भी उत्कृष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने धैर्य को अपना गहना बनाया है।

धैर्यवान व्यक्ति में अनुशासन को बनाए रखने की प्रगाढ़ क्षमता होती है और वह इतना संतुलित होता है कि हमेशा दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। वह जहां भी जाता है, दूसरों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है और अपनी बातचीत तथा उच्च विचारों से चंदन की भांति दूसरों को शीतलता प्रदान करता है। धैर्य हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करने में मदद करता है और उस सर्वशक्तिमान और निराकार ऊर्जा में विलीन कर देता है, जो मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती है। धैर्य को योग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि योग मानसिक एकाग्रता को गति प्रदान करता है तथा धीरे-धीरे धैर्य रूपी सकारात्मक गुण को बढ़ाता चला जाता है। कोई भी इंसान अपने जीवन को स्वस्थ और शांतिमय तरीके से जीने की चेष्टा करता है। धैर्य व्यक्ति को हृदय के स्तर पर शांति प्रदान करने का काम करता है। अगर कोई भी मनुष्य शांत कमरे में विराजमान है, मगर उसका हृदय शांत नहीं है तो उसे आंतरिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

सौरभ पाठक

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

मोदी विरोध के लिए संसद ही क्यों?

पंद्रह मिनट के संबोधन की प्रतीक्षा शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजीव सचान ने राहुल गांधी की बौखलाती विचारशीलता को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया है, वह अत्यंत रोचक है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संसद को ही उपयुक्त क्यों मान रहे हैं? यदि उनके पास मोदी सरकार की पोल खोलने वाला कोई ऐसा मसाला है, जो भूचाल ला सकता है तो उसे संसद से बाहर किसी अन्य मंच पर सार्वजनिक करने से परहेज क्यों किया जा रहा है? हां! यदि संसद में ही मोदी पर प्रहार करने का कोई विशेष शगुन है तो अभी हाल में बिना किसी चर्चा के विदा होने वाले संसद के बजट सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसा करने से किसने रोका था? पीएनबी बैंक घोटाले के साथ विगत में हुई नोटबंदी से हुए नफा-नुकसान पर राहुल गांधी बजट सत्र में खुलकर बहस करके मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन उस समय राहुल गांधी की चुप्पी के साथ व्यर्थ का विपक्षी हंगामा देश को हैरान करता रहा। सत्ता पक्ष में बैठी हुई भाजपा के विगत चार वर्ष के लेखे-जोखे के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की वैचारिकी को संसद के अंदर और बाहर केवल पंद्रह मिनट नहीं अपितु घंटों सुनने के लिए देश की जनता लालायित है, लेकिन चाहे कोई संसदीय सत्र हो अथवा सार्वजनिक मंच राहुल गांधी ने इस वैचारिक मुद्दे पर देश की आम जनता को हमेशा निराश ही किया है। कांग्रेस अध्यक्ष की यह विचार शून्यता देश को हैरान करती है, क्योंकि अब राहुल गांधी को उस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसने अपनी राजनीतिक चतुराई से लगभग 60 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है। pandeyvp1960@gmail.com

भारत-पाक के दोस्त

दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण देश भारत व पाकिस्तान के दोस्त बदलने और पुराने दोस्तों से दूरियां बढ़ने के संकेत साफ दिख रहे हैं। पाकिस्तान व अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट आई है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते में गर्मजोशी आई है। दूसरी तरफ भारत के पारंपरिक साथी रहे रूस की दिलचस्पी पाकिस्तान में बढ़ी है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि अगर भारत नए विकल्पों की तरफ रुख कर सकता है, तो रूस भी ऐसा कर सकता है। रूस-पाक रिश्तों के आने वाले समय में और अधिक फलने- फूलने की संभावना है। दोनों देशों में अमेरिका विरोधी भावना जबरदस्त थी और दोनों को करीब लाने में इसी भावना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाक-रूस नीति-नियंताओं को लगता है कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए अमेरिका के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। a.satya.gnitw011@gmail.com

पुलिस की जिम्मेदारी

दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं ने देश के सभ्य समाज की संरचना पर कुठाराघात किया है। हमारे समाज के कुछ लोग इस तरह की घटनाओं के लिए पाश्चात्य संस्कृति को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन क्या भारतीय संस्कृति के अनुसार रहने वाली महिलाएं सुरक्षित हैं? इसी समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। पुलिस को ईमानदारी से जांच करनी होगी। शैलेंद्र सिंह, भारतीय विधा भवन

फर्जी विश्वविद्यालय

प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय फर्जी विवि की एक सूची जारी करते हैं। मैं पिछले आठ साल से इस प्रकाशित सूची को पढ़ रही हूं, जिसमें क्रमशः उन्ही नामों की ही पुनरावृत्ति हो रही है। यह ठीक है कि यूजीसी छात्रों को चेतावनी दे रहा है, क्या सूची प्रकाशित कर देने भर से यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय जिम्मेदारी से बच जाएंगे? rachnadublish@gmail.com

भारत -चीन द्विपक्षीय संबंध

भारत के दो केंद्रीय मंत्री का चीन में होना यह दर्शाता है कि भारत और चीन के रिश्तों में कुछ तो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 1950 में भारत व चीन के बीच हुए राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से ही दोनों के रिश्ते कभी सीधी रेखा पर नहीं चले। यूं तो सुषमा स्वराज व निर्मला सीतारमण शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सेदारी करने गई हैं, लेकिन उनकी यात्रा का मूल मकसद भारतीय प्रधानमंत्री व चीनी राष्ट्रपति की प्रस्तावित मुलाकात की जमीन तैयार करना है। चीनी विदेश मंत्री ने भी दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की प्रस्तावित मुलाकात को रिश्तों में नया मोड़ लाने वाला करार दिया है। भेंट से पूर्व ही चीन ने लंबे समय की भारतीय मांग को मानते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े आंकड़े भारत के साथ साझा करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही मानसरोवर यात्रा के लिए नाथू-ला दर्रे के रास्ते दोबारा शुरू करने पर चीन राजी दिख रहा है। इस बदली हुई पृष्ठभूमि में डोकलाम के मौजूदा हालात, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, एनएसजी में भारत की सदस्यता व पाक समर्थित आतंकवाद पर किसी ठोस नतीजे की अपेक्षा की जा सकती है। अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप चीन द्वारा अमेरिकन उत्पादों पर हाई टैरिफ लागू करने से दोनों ही देशों के बीच व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत के पास अवसर है कि वह बड़े पैमाने पर चीन को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी भारत को भारत-चीन-नेपाल के बीच प्रस्तावित आर्थिक गलियारे को लेकर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिये चीन नेपाल के तराई क्षेत्र तक अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। उसका इरादा नेपाल को भी पाकिस्तान की ही भांति अपने कर्ज तले दबाने का है। ऐसे में भारत को रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने के साथ ही सतर्क रहना होगा। अभय नाथ झा, नोएडा

ट्वीट-ट्वीट

डेरा प्रमुख गुरमीत रहीम के बाद एक और दुष्कर्मी बाबा को सजा मिली। पीड़िता के साथ इंसाफ हुआ। हमें ऐसे स्वयंभू भगवानों की जरूरत नहीं। वे समाज को शर्मसार ही करते हैं।
साध्वी खोसला@sadhavi

आसाराम मामले में बहादुर लड़की और उसके परिवार की दाद देनी होगी जिन्होंने सभी तरह के दबावों का सामना किया जिसमें तमाम गवाह मारे गए और कुछ अब भी गायब हैं। उनके वकील ने इसकी बखूबी पैरवी की।
स्मिता शर्मा@Smita_Sharma

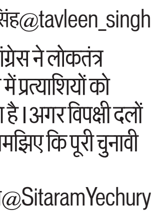

सलमान खुर्शीद ने हैरतअंगेज रूप से बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से सने हैं। लगे हाथों वह यह भी बता देते तो बेहतर होता कि देश की सबसे 'सेक्युलर' पार्टी के दामन पर सिखों के खून के दाग भी लगे हैं।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लोकतंत्र की ऐसी हत्या की है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को वाट्सएप्प से नामांकन कराना पड़ रहा है। अगर विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को ऐसा करने पड़े तो समझिए कि पूरी चुनावी प्रक्रिया ही मजाक बन गई है।
सीताराम येचुरी@SitaramYechury

जनपथ

मन भटका तो साधु को रहा न तन का होश,
आखिर साबित हो गया उनका सारा दोष।
उनका सारा दोष कोर्ट ने सजा सुनाई,
कर्मों का फल जाय जेल में भोगो भाई।
बापू आशाराम खा गए तगड़ा झटका,
कथा सुनाय सुनाय न जाने कब मन भटका!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 281**